नईदुनिया

भोपाल, 18 अगस्त 2026

एलपीजी ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़कर 23 अगस्त हुई

सर्वर और एप में तकनीकी खराबी से उपभोक्ता परेशान, गैस एजेंसियों पर बढ़ी भीड़

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: घरेलू एलपीजी सिलेंडर की ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त से बढ़ाकर 23 अगस्त 2026 कर दी गई है। समय सीमा बढ़ने के बावजूद तेल विपणन कंपनियों के सर्वर और आधिकारिक मोबाइल एप में तकनीकी समस्याओं के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर डाउन रहने और एप के ठीक से काम नहीं करने से कई लोगों का सत्यापन पूरा नहीं हो पा रहा है। गैस एजेंसियों के काउंटरों पर लंबी कतारें लगी हैं।

तेल विपणन कंपनियों ने आधार सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 23 अगस्त कर दी है। इससे उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी पूरी करने के लिए सात दिन का अतिरिक्त समय मिला है। हालांकि, डीलरों के अनुसार तकनीकी समस्याएं बनी हुई हैं। सर्वर बंद होने पर पूरे दिन का काम प्रभावित होता है और लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है।

गैस एजेंसियों पर पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। काउंटर तक पहुंचने के बाद भी सर्वर ठप होने से बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं हो पा रहा है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया तेल कंपनियों के केंद्रीय डिजिटल ढांचे और सर्वर पर निर्भर है। मुख्य सर्वर में समस्या या एप की धीमी प्रक्रिया से पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है।

उपभोक्ता संबंधित गैस कंपनी के आधिकारिक मोबाइल एप के माध्यम से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। इंडेन, एचपी और भारत गैस के एप में ई-केवाईसी का विकल्प उपलब्ध है। फेस सत्यापन करते समय पर्याप्त रोशनी और मोबाइल को स्थिर रखना जरूरी है। फेस स्कैन के बाद एप में ई-केवाईसी सफल होने का संदेश देखना आवश्यक है। केवल फेस स्कैन हो जाने से प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी।

यदि मोबाइल एप से ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो उपभोक्ता गैस एजेंसी जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। इसके अलावा सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले कर्मचारी के पास उपलब्ध आधिकारिक उपकरण से भी बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जा सकता है। नियमों के अनुसार 23 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ता अस्थायी रूप से घरेलू या रियायती दरों पर सिलेंडर पाने का अधिकार खो सकते हैं। ई-केवाईसी पूरी होने तक उन्हें व्यावसायिक दर पर सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है। हालांकि, इससे गैस कनेक्शन रद्द नहीं होगा।

बैंकिंग सुधारों के लिए जल्द बनेगी उच्चस्तरीय समिति

बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत, विकसित भारत पर रहेगा ध्यान:निर्मला सीतारमण

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सरकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए जल्द ही उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के पहले दिन यह घोषणा की। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार, समिति का गठन इसी महीने किया जा सकता है।

उच्चस्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2026-27 में रखा गया था। वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका की समीक्षा के लिए इस समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को देश के आर्थिक विकास की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना और उसमें आवश्यक सुधारों की समीक्षा करना होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि समिति का मुख्य ध्यान वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के

लक्ष्य में बैंकों की भूमिका पर रहेगा। उन्होंने कहा कि 2047 अब बहुत दूर नहीं है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को अपनी भूमिका के अनुरूप तैयार करना आवश्यक है।

सीतारमण ने बैंकिंग क्षेत्र में पिछले वर्षों के सुधारों और बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में आए बदलाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों को लागू करने में सरकार देरी नहीं करेगी। समिति के सुझाव प्राप्त होते ही उन पर तेजी से काम किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी बैंकों ने कुल मिलाकर 1.98 लाख करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। बैंकों की मजबूत वित्तीय स्थिति के बीच सरकार अब बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का विकसित भारत 2047 का लक्ष्य देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास और बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। बैंकों की वित्तीय स्थिति का आकलन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए से भी किया जाता है। एनपीए ऐसे ऋण या अग्रिम होते हैं, जिनका ब्याज या मूलधन सामान्यत: 90 दिन तक नहीं चुकाया जाता। बैंकों का एनपीए कम होना उनकी बेहतर वित्तीय स्थिति का संकेत माना जाता है।

खास-खबरें

टीसीएस-रिलायंस में 66 हजार करोड़ रुपये की गिरावट

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: शेयर बाजार में बीते सप्ताह रही गिरावट के बीच देश की प्रमुख कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला। टाटा समूह की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों को पांच कारोबारी दिनों में 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। दूसरी ओर, भारतीय जीवन बीमा निगम समेत पांच प्रमुख कंपनियों के बाजार मूल्य में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते सप्ताह सेंसेक्स में करीब 490 अंकों और निफ्टी में 205 अंकों की गिरावट रही। इस दौरान टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 34,263.28 करोड़ रुपये घटकर 8,53,506.85 करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 31,869.13 करोड़ रुपये घटकर 17,70,056.06 करोड़ रुपये रह गया। दोनों कंपनियों के बाजार मूल्य में कुल 66,132 करोड़ रुपये से अधिक की कमी आई। बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में भी गिरावट रही। भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण 25,891.88 करोड़ रुपये घटकर 9,85,829.96 करोड़ रुपये रह गया। एचडीएफसी बैंक के बाजार मूल्य में 7,165.37 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक के बाजार मूल्य में 2,792.65 करोड़ रुपये की कमी आई।

दूसरी ओर, भारतीय जीवन बीमा निगम के बाजार पूंजीकरण में 26,438.49 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 5,23,330.31 करोड़ रुपये पहुंच गया। भारती एयरटेल का बाजार मूल्य 20,592.13 करोड़ रुपये बढ़कर 12,43,016.11 करोड़ रुपये हो गया। बजाज फाइनेंस के बाजार पूंजीकरण में 3,548.79 करोड़ रुपये, एलएंडटी में 2,490.66 करोड़ रुपये और हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2,079.38 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई।

टेम्पसेंस इंस्ट्रुमेंट्स का आईपीओ 20 अगस्त को खुलेगा, मूल्य दायरा 285-300 रुपये प्रति शेयर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: टेम्पसेंस इंस्ट्रुमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 20 अगस्त को खुलेगा। इसमें निवेश करने के लिए निवेशक 24 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं। एंकर निवेशक 19 अगस्त को बोली लगा सकते हैं। इसके लिए मूल्य दायरा (प्राइस बैंड) 285-300 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। टेम्पसेंस इंस्ट्रुमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड के 650 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में करीब 95 करोड़ रुपये के नए शेयर तथा 1.85 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। निवेशक इसमें कम से कम 50 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 50 के मल्टीपल में बोली लगा सकते हैं।कंपनी की योजना इस इश्यू से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने, कर्ज चुकाने और कंपनी के सामान्य कामकाज के लिए किया जाएगा। कंपनी का शेयर 28 अगस्त को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990 में स्थापित टेम्पसेंस इंस्ट्रुमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड एक प्रमुख थर्मल इंजीनियरिंग और विशेष केबल समाधान प्रदाता कंपनी है। कंपनी 31 मार्च तक भारत में फाइबर ऑप्टिक टेम्परेचर सेंसर और थर्मल प्रोफाइलिंग सिस्टम बनाने वाली एकमात्र कंपनी भी है, और फिस्कल ईयर 2026 में भारत में पाइरोमीटर और ऑनलाइन थर्मल इमेजर बनाने वाली एकमात्र कंपनी है।

एफडीए की कार्रवाई स्वागत योग्य, कानून से ऊपर कोई नहीं : खंडेलवाल

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन एवं टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के प्रचार-प्रसार से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया जाना बहुत ही कानून सम्मत एवं एक स्वागतयोग्य कदम है। सांसद एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही है। सांसद एवं कैट महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने सोमवार को कहा कि यह संदेश स्पष्ट रूप से जाना चाहिए कि देश में कानून, नियम और उपभोक्ता हित सर्वोपरि हैं तथा किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता या सेलिब्रिटी हैसियत उसे कानूनों के पालन से छूट नहीं दे सकती।

भारत की इलेक्ट्रिक कारों की विदेशों में बढ़ी मांग

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत से इलेक्ट्रिक कारों के निर्यात में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात 369 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 22.2 मिलियन डॉलर था। निर्यात की संख्या भी 1,309 से बढ़कर 10,802 वाहन हो गई। यूरोप भारतीय इलेक्ट्रिक कारों का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। स्पेन भारतीय इलेक्ट्रिक कारों के लिए सबसे बड़ा खरीदार रहा। पहली तिमाही में स्पेन को 146.4 मिलियन डॉलर मूल्य की 4,007 इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात किया गया। यह कुल निर्यात का करीब 40 प्रतिशत है। मूल्य और वाहनों की संख्या, दोनों के लिहाज से स्पेन सबसे आगे रहा।

ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा। वहां 78.7 मिलियन डॉलर मूल्य की इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात हुआ। पिछले वर्ष की समान अवधि में ब्रिटेन को केवल एक इलेक्ट्रिक कार भेजी गई थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 2,646 हो गई।

यूरोप के अन्य देशों में भी भारतीय इलेक्ट्रिक कारों की मांग में वृद्धि हुई है। जर्मनी को 25.1 मिलियन डॉलर, नॉर्वे को 21.1 मिलियन डॉलर और डेनमार्क को 21 मिलियन डॉलर मूल्य की इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात किया गया।

एलपीजी किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने तय किए उत्पादन लक्ष्य

21 कंपनियों को रोजाना 63,810 टन एलपीजी उत्पादन का लक्ष्य, आयात पर निर्भरता घटाने की तैयारी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: मध्य पूर्व में तनाव और युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति पर पड़े असर से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने देश की सरकारी और निजी रिफाइनरियों तथा अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए एलपीजी उत्पादन के अधिकतम लक्ष्य तय किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 13 अगस्त को जारी आदेश में 21 कंपनियों के लिए कुल 63,810 टन प्रतिदिन एलपीजी उत्पादन की क्षमता और लक्ष्य निर्धारित किया है।

यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश में हुए कुल घरेलू एलपीजी उत्पादन 35,900 टन प्रतिदिन से दोगुने से अधिक है। निर्धारित उत्पादन लक्ष्य देश की कुल दैनिक खपत का करीब 70 प्रतिशत पूरा कर सकता है। बाजार में गैस की कमी या आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में यह व्यवस्था लागू होगी।

सरकार के आदेश के अनुसार, निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की

गुजरात स्थित जामनगर घरेलू टैरिफ क्षेत्र रिफाइनरी को सबसे बड़ा 18,000 टन प्रतिदिन एलपीजी उत्पादन लक्ष्य दिया गया है। रूस की रोसनेफ्ट समर्थित नयारा एनर्जी की वाडीनार रिफाइनरी को 4,480 टन प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य मिला है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में कुल 3.32 करोड़ टन एलपीजी की खपत हुई थी। इसमें 1.31 करोड़ टन घरेलू उत्पादन हुआ, जबकि 2.13 करोड़ टन एलपीजी का आयात करना पड़ा। यानी देश की जरूरत का 64 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात से पूरा हुआ। ईरान युद्ध के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता बाधित होने से एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हुई थी।

मध्य पूर्व संकट के दौरान मार्च में सरकार को पेट्रोकेमिकल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली गैस को एलपीजी बनाने के लिए भेजना पड़ा था। घरेलू उत्पादन बढ़ाकर 55,000 टन प्रतिदिन किया गया था। उस दौरान वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री रोकने, घरेलू एलपीजी रीफिल की बुकिंग का समय बढ़ाने और पाइप से मिलने वाली गैस के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए गए थे।

मंत्रालय ने कंपनियों को एलपीजी भंडारण, निकासी और रेल तथा सड़क टैंकरों के लिए पर्याप्त ढांचा विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उत्पादन कार्यक्रम की हर छह महीने में समीक्षा होगी और इसे हर साल एक जनवरी तथा एक जुलाई को अद्यतन किया जाएगा।

महिंद्रा ने ब्लेजो आई-टीआरके ट्रक किया पेश

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में ब्लेजो आई-टीआरके ट्रक पेश किया है। कंपनी का दावा है कि यह ट्रक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक से लैस है और परिवहन कारोबार में वाहन की उपलब्धता बढ़ाने के साथ परिचालन लागत कम करने में मदद करेगा। कंपनी के अनुसार, इस ट्रक के माध्यम से परिवहन कारोबारियों को पांच वर्षों में करीब 15 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आय हो सकती है। ब्लेजो आई-टीआरके को विशेष रूप से भारी और लंबी दूरी के परिवहन कार्यों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो वाहन के प्रदर्शन और परिचालन से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने में मदद करती है। कंपनी के अनुसार, तकनीक के माध्यम से वाहन के रखरखाव और संचालन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।कंपनी ने ट्रक के साथ उपलब्धता की गारंटी भी पेश की है। इसके तहत यदि वाहन किसी खराबी के कारण निर्धारित अवधि में सड़क पर उपलब्ध नहीं रहता है, तो ग्राहक को प्रतिदिन 10 हजार रुपये तक की राशि मिलने का दावा किया गया है। कंपनी का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य परिवहन कारोबारियों को वाहन के लंबे समय तक बंद रहने से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। महिंद्रा के अनुसार, ट्रक में ऐसी तकनीक और सुविधाएं दी गई हैं, जो वाहन के संचालन, रखरखाव और ईंधन दक्षता को बेहतर बनाने में सहायता करती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली वाहन के प्रदर्शन की निगरानी करने और संभावित समस्याओं की पहचान करने में मदद कर सकती है।कंपनी का मानना है कि वाणिज्यिक वाहन कारोबार में वाहन का सड़क पर उपलब्ध रहना सीधे तौर पर कमाई से जुड़ा होता है।

कंपनी का दावा, वाहन खराब रहने पर रोजाना 10 हजार रुपये तक की आय की गारंटी

सोना 1,703 रुपये बढ़कर 1.54 लाख रुपये पर पहुंचा

अगस्त में अब तक सोना 11 हजार और चांदी 18 हजार रुपये महंगी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को तेजी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,703 रुपये बढ़कर 1.54 लाख रुपये पर पहुंच गया। वहीं, एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2,531 रुपये बढ़कर 2.36 लाख रुपये हो गई। अगस्त में अब तक सोने की कीमत करीब 11 हजार रुपये और चांदी की कीमत 18 हजार रुपये बढ़ चुकी है। इस साल सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोने की कीमत 1.33 लाख रुपये से अधिक थी, जो अब बढ़कर 1.54 लाख रुपये हो गई है। इस तरह वर्ष 2026 में सोना अब तक करीब 21 हजार रुपये महंगा हुआ है। चांदी की कीमत भी 31 दिसंबर 2025 के 2.30 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2.36 लाख रुपये हो गई है।

29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपये और चांदी ने 3.86 लाख रुपये का सर्वकालिक उच्च स्तर दर्ज किया था।

वस्तु बाजार विशेषज्ञ अजय केडिया के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ चुकी हैं। ऐसे में निवेशक इनमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन एकमुश्त निवेश से बचना चाहिए। उनके अनुसार, वर्ष के अंत तक सोना फिर 1.60 लाख रुपये और चांदी 2.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है।

आभूषण खरीदते समय भारतीय मानक ब्यूरो का हॉलमार्क लगा प्रमाणित सोना ही खरीदना चाहिए। सोने का वजन और खरीद के दिन की कीमत अलग-अलग स्रोतों से जांचना भी जरूरी है। 24, 22 और 18 कैरेट सोने के भाव अलग होते हैं। असली चांदी की पहचान के लिए चुंबक, बर्फ, गंध और कपड़े से रगड़ने जैसे परीक्षण किए जा सकते हैं। असली चांदी चुंबक से नहीं चिपकती और उस पर बर्फ तेजी से पिघलती है।

501 दिन की सावधि जमा पर 8 प्रतिशत तक ब्याज

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सावधि जमा में निवेश करने वाले ग्राहकों के लिए 501 दिन की विशेष जमा योजना आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। छोटी वित्त बैंक की विशेष सावधि जमा योजनाओं में 501 दिन की अवधि पर सामान्य ग्राहकों को 8 प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ बैंकों में यह दर और अधिक है। 501 दिन की अवधि वाली सावधि जमा योजना में निवेश की अवधि करीब एक वर्ष चार महीने होती है। इस तरह की योजनाएं उन निवेशकों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं, जो लंबी अवधि के बजाय सीमित समय के लिए अपनी राशि सुरक्षित रखकर निश्चित ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। यदि पांच लाख रुपये की राशि सावधि जमा में लगाई जाती है, तो मिलने वाला लाभ बैंक की ब्याज दर और ब्याज की गणना की पद्धति पर निर्भर करेगा।

पश्चिम बंगाल में महंगी हुई ब्रेड, कीमत 32 से बढ़कर 36 रुपये

नईदुनिया ब्यूरो, कोलकाता: पश्चिम बंगाल में ब्रेड की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल बेकर्स एसोसिएशन ने एक पाउंड ब्रेड की कीमत 32 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये कर दी है। नई कीमतें 17 अगस्त से लागू हो गई हैं।एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरिफुल इस्लाम ने बताया कि कीमत बढ़ाने का निर्णय आठ अगस्त को हुई कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया था। उन्होंने कहा कि आटा, चीनी और पैकेजिंग सामग्री की लागत लगातार बढ़ने के कारण यह फैसला लेना पड़ा। एसोसिएशन ने कुछ समय तक कीमत बढ़ाने से बचने का प्रयास किया, लेकिन बढ़ती उत्पादन लागत के कारण ऐसा करना संभव नहीं रहा।

सेंसेक्स 280 अंक गिरकर 77,728 पर बंद

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट रही। सेंसेक्स 280 अंक टूटकर 77,728 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी में करीब 78 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,287 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में आईटी और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली।

सोमवार से दो आरंभिक सार्वजनिक निर्गम खुले हैं। होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स और ललिता ज्वेलरी मार्ट के निर्गम में निवेशक 19 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। ललिता ज्वेलरी मार्ट के जरिए 1,700 करोड़ रुपये और होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स के जरिए 2,600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। दूसरी ओर, एशियाई बाजारों में सोमवार को तेजी रही। दक्षिण कोरिया का

निफ्टी में भी 78 अंकों की गिरावट, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली

कोस्पी 165 अंक बढ़कर 6,978 के स्तर पर पहुंचा। जापान का निक्केई 506 अंक बढ़कर 69,220 और हांगकांग का हैंगसेंग 336 अंक की बढ़त के साथ 25,453 के स्तर पर रहा।

इससे पहले 14 अगस्त को अमेरिकी बाजारों में गिरावट रही थी। डाउ जोन्स 108 अंक गिरकर 53,732, नैस्डैक 74 अंक टूटकर 26,729 और एसएंडपी 500 सूचकांक 13 अंक की गिरावट के साथ 7,786 के स्तर पर बंद हुआ था।विदेशी निवेशकों ने पिछले सात दिनों में भारतीय शेयर बाजार से 747 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं। हालांकि, पिछले 30 दिनों में विदेशी निवेशकों की खरीदारी 2,884 करोड़ रुपये रही। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने पिछले सात दिनों में 10,576 करोड़ रुपये और पिछले 30 दिनों में 31,078 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इससे पहले शुक्रवार, 14 अगस्त को भी घरेलू बाजार में गिरावट रही थी। सेंसेक्स 70 अंक गिरकर 79,009 और निफ्टी 29 अंक टूटकर 24,366 के स्तर पर बंद हुआ था।

स्पेशल खबर — मुख्य आर्थिक सलाहकार ने पुराने दोपहिया वाहनों के लिए ई10 पेट्रोल फिर शुरू करने की सलाह दी

ई20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों को नुकसान की आशंका

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने ई20 पेट्रोल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने पुराने दोपहिया वाहनों के लिए ई10 पेट्रोल की बिक्री फिर शुरू करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने से पुराने कार्बोरेटर वाले वाहनों को परेशानी हो सकती है। भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है, जिससे कच्चे तेल के आयात में कमी और विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

नागेश्वरन के अनुसार, देश में करीब आठ करोड़ पुराने बाइक और स्कूटर हैं, जो कार्बोरेटर तकनीक पर चलते हैं। ई20 पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा अधिक होने के कारण इन वाहनों के इंजन को ईंधन के नए मिश्रण

के अनुसार समायोजित करने में कठिनाई हो सकती है। इससे इंजन अधिक गर्म होने और रबर के पाइप तथा अन्य हिस्सों के खराब होने का खतरा है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक पुराने वाहनों में आवश्यक बदलाव नहीं किए जाते, तब तक ई10 पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए।

एथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इससे खाद्य क्षेत्र पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है। यदि एथेनॉल कंपनियां अधिक कीमत पर मक्का खरीदती हैं, तो पोल्ट्री और डेयरी उद्योग के लिए चारा महंगा हो सकता है। इससे अंडे, चिकन और दूध की कीमतें बढ़ सकती हैं।

एथेनॉल उत्पादन में गन्ने के इस्तेमाल से चीनी की उपलब्धता और पानी की खपत को लेकर भी चिंता है। इस मौसम में देश के कुल वार्षिक उत्पादन की करीब 10 प्रतिशत चीनी, लगभग 30 लाख टन, एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने की बात कही गई है। गन्ने की खेती में बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इसलिए एथेनॉल उत्पादन के साथ भूजल पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखने की जरूरत बताई गई है।

सरकार ने दूसरी ओर ई20 को सुरक्षित बताया है। उसका कहना है कि एथेनॉल मिश्रण से विदेशी मुद्रा की बचत और किसानों को बेहतर कीमत मिल रही है। सरकारी परीक्षणों में ई20 से बड़े पैमाने पर इंजन क्षति के प्रमाण नहीं मिले हैं। अलग-अलग ई10 और ई20 पेट्रोल की उपलब्धता को लेकर सरकार का तर्क है कि इससे आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था की लागत बढ़ेगी। नागेश्वरन ने एथेनॉल योजना बंद करने की बात नहीं कही है, बल्कि 20 प्रतिशत मिश्रण के बाद इसके प्रभावों का सावधानी से आकलन करने की आवश्यकता बताई है।